**Compensation by the State to the Victims of hit-and-run Cases**

9456. SHRI D. K. PANDA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Law Commission has recommended that State should undertake the responsibility to compensate the victims of hit-and-run cases of car accidents; and

(b) if so, what decision has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI M. B. RANA): (a) Yes, Sir.

(b) Since the implementation of the recommendation of the Law Commission involves amendment to the Motor Vehicles Act, 1939, it is being circulated to the State Governments and Union Administrations for comments, as suggested by the Commission themselves. A decision will be taken after comments are received from the State Governments etc.

---

12 Hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**Reported consensus on Cauvery Waters between the Chief Ministers of Tamil Nadu, Mysore and Kerala**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): अध्यक्ष महोदय, मै अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सिचाई और विद्युत मत्री का ध्यान दिलाता हू और प्रार्थना करता हू कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दे·

"कावेरी तथ्य जांच समिति द्वारा कावेरी जल के सबंध मे की गई परिगणना के बारे मे तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुख्य मत्रियो के बीच मतैक्य का समाचार"

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA): There have been differences amongst the States of Kerala, Mysore and Tamil Nadu for a number of years on the Cauvery waters. The discussions held in May, 1972 amongst the Chief Ministers revealed the general consensus that a serious attempt should be made to resolve the dispute by negotiations as early as possible. There was also consensus that the Centre should appoint a Fact Finding Committee to collect all the connected data pertaining to Cauvery waters, their utilisation and irrigation practices as also about projects both existing, under construction and proposed in the Cauvery basin. The Committee should also examine the adequacy of the present supplies or excessive use of water for irrigation purposes.

A Fact Finding Committee was accordingly set up by Government of India on 12th June, 1972 and had the following composition :—

1. Shri Justice B. D. Bal—Retd. Judge of Bombay High Court.
2. Shri P. R. Ahuja —Retd. Commissioner (Indus) and Joint Secretary, Ministry of Irrigation and Power.
3. Shri Jatindra Singh —Retd. Chief Engineer, Punjab.
4. Dr. J. S. Patel —Retd. Agricultural Commissioner, Ministry of Food & Agriculture.

The Committee submitted its report in December, 1972, which contains the necessary data on the availability of waters, existing utilisation as reported to the Committee, utilisation proposed from projects under construction and the utilisation envisaged from future projects contemplated by the three States.

There were discussions with the Chief Ministers of Kerala, Mysore and Tamil Nadu on 29th April, 1973 about the report of the Committee. During these discussions, there was a general consensus

[Shri Balgovind Verma]

on the total yield of the river as given in the Committee's Report As desired by the Chief Ministers, the Committee is being revived to furnish clarifications on some other points after such varification as is found necessary

The Chief Ministers agreed to meet at a later date to continue the discussions and explore the possibilities of arriving at a settlement.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** अध्यक्ष महोदय कावेरी हमारी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नदियो मे से है। केरल मैसूर और तमिलनाडु का प्रदेश कावरी के द्वारा अभिसिंचित होता है। इन प्रदेशो मे इस नदी के जल विवाद को ले कर काफी दिनो स विवाद चल रहा है। मत्री महादय न इस वक्तव्य म कहा है कि अभी 29 अप्रल का जा मुख्य मत्रिया की बैठक हुई थी उस मे इस सवाल पर मतैक्य हो गया कि कावरी म से कुल कितना जल उपलब्ध होगा। यह तथ्य तो फैक्ट फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनसार सामने आ गय है लेकिन क्या यह आश्चर्य की बात नही है कि विवाद इतन वर्षों से चल रहा है और सैंट्रल वाटर एड पावर कमिशन या सरकार के किसी अन्य एजसी न यह पता तक लगाने का प्रय न नहा किया कि जिस पानी के लिये झगडा हो रहा है वह कुल कितना है? अब फैक्ट फाइडिंग कमेटी बनी है उस न कहा है कि पानी कुल 21 मिलियन क्यूबिक मीटर उपलब्ध है, लकिन तीनो राज्य जो पानी माग रहे हैं वह 35 मिलियन क्यूबिक मीटर है। मुझ तो लगता है कि मुख्य मत्रियो की बैठक विफल हो गई या फिर मुख्य मत्रियो की बैठक न जो विवाद का मुख्य मुद्दा है उस को स्पश करने की आवश्यकता ही नही समझी। मुख्य मुद्दा यह है कि पानी का वितरण किस हिसाब से हो।

तमिलनाडु कह रहा है कि कावरी क पानी के सबध मे 1924 मे और उस से भी पहले 1892 मे समझौता हुआ था। यह समझौता मद्रास और मैसूर के बीच मे हुआ था। उस समझौत के अनुसार तमिलनाडु ने सिचाई के प्रबन्धो का विकास किया और अब तमिलनाडु यह चाहता है कि ऐसा समझौता हो जिस से तजोर और तिचुरापल्ली जिलो का जो भूखण्ड है, जो कावेरी के जल से सिचित हो रहा है, उस भूखण्ड को जल से वचित न रहना पडे। तमिलनाडु यह भी चाहता है कि जब तक विवाद तय न हो तब तक मैसूर की कावेरी या उस से जुडी हुई नदियो पर नई परियोजनाये बनने से रोक दी जायें। इस के विपरीत मैसूर का कहना यह है कि 1424 का जो समझौता था वह असामान्य समझौता था, उस मे मैसूर का पक्ष ठीक तरह से नही रखा गया था। मैसूर अब नई योजनाये हाथ मे ल रहा हैं। वह 1924 के ऐग्रीमेंट से बंधा रहन के लिये तैयार नही है। उसने कई योजनाये अपन हाथ मे ली हैं। हेमावती हरगी और कबीनी परियोजनाये दस वर्षों से चल रही हैं। इन परियोजनाओ के लिये प्लैनिंग कमीशन की स्वीकृति नही ली गई। परियोजनाओ को पूरा करने मे धन का अभाव है लेकिन मैसूर अपने हित की दृष्टि से इन परियोजनाओ को पूरा करना चाहता है।

तीसरी ओर केरल का सवाल है। जब मद्रास और मैसूर का समझौता हुआ तो केरल की उपेक्षा की गई। केरल का दावा यह है कि पानी सब स ज्यादा वहा बरसता है इसलिये कावेरी का पानी दने म उस का सब स ज्यादा योगदान है

> "One-third of the run off of the basin is made by the catchment area lying in the State on account of the very heavy rainfall"

मैं जानना चाहता हू कि जल के वितरण के सम्बन्ध म जो विवाद है वह कैसे हल होगा? मत्री महादय ने कहा कि फैक्ट फाइडिंग कमेटी को रिवाइव किया जा रहा है

> 'As desired by the Chief Ministers the Committee is being revived to furnish clarifications on some other points after such verifications as are found necessary"

मैं जानना चाहता हू कि वह कौन सा क्लैरिफिकेशन है जो मागा गया है और कौन से वेरिफिकेशन्स

हैं जिन की आवश्यकता है। क्या इस में जल के वितरण का भी सवाल है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि यह नदी तीन प्रदेशों की सिंचाई करती है, इस लिये अभी तक विवाद को हल क्यों नहीं किया गया ? जब वितरण का प्रश्न आयेगा तब केन्द्र द्वारा नये मुद्दे खड़े किये जायेंगे। क्या इस मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह भी चर्चा की गई कि अगर अन्ततोगत्वा तीनों मुख्य मंत्रियों का समझौता न हुआ तो इस मामले को ट्राइब्यूनल को सौंप दिया जाये ? संसद् इस तरह का कानून बना चुकी है और ट्रिब्यूनल का निर्णय तीनों पक्षों को मान्य होगा, इस बात की मांग की जा सकती है। तीनों पक्ष उस को मानने से बंधे भी हुए हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक यह विवाद चलता रहेगा और कब तक हम राष्ट्रीय जल का पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहेंगे। क्या आगे मुख्य मंत्रियों की बैठक के लिए कोई तारीख भी तय हुई है या नहीं ? जो पिछली बैठक हुई है, क्या उस में वितरण के बारे में भी कोई चर्चा हुई है ? धारणा यह बनी है कि मुख्य मंत्रियों में कानसेन्सस हो गया है। किस बारे में कानसेन्सस हो गया है ? कानसेन्सस तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हुआ है कि कितना पानी उपलब्ध है ? लेकिन झगड़ा है पानी के वितरण के बारे में और वह झगड़ा अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि सारा मामला ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाये, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का हल निकाला जाये और जब तक ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं देता, तब तक जहां परियोजनायें बना कर भूमि सींची जा रही है, चाहे वह मैसूर में हो और चाहे तामिलनाडु में हो,—और वह अधिकतर तामिलनाडु में है, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है—वहां सिंचित भूमि को असिंचित बनाने के लिए कोई प्रयत्न न किया जाये ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): As the hon. Member has said, the Cauvery is one of our most ancient and sacred rivers, and one of those rivers in the world, of whose waters much use has been made. The hon. Member has mentioned various difficulties that have arisen in the Cauvery system. There are three aspects which have got to be resolved in any river dispute. The first is the quantum of water which is there in the river. That is the first aspect which has got to be decided. The second is the allocation among the different contending parties, namely how much amount of water should be allocated to one State, how much to the other and so on. The third is the regulation, that is, how the regulation of the water is to be done so that each of the contending parties will get the water which has been allocated. These are the three important aspects which have to be settled in any river dispute.

There are a number of disputes where there has been difficulty in fixing the quantum of water. For example, in the Krishna river, more than four years have passed in the Tribunal trying to find out the quantum of water which is there in the river. That is one of the very difficult items to be settled. The Government of India have only recently been able to survey some of the basins of the river. This problem arises in regard to the various rivers flowing through the various States.

Therefore, wherever there is a river dispute, the first question that presents considerable difficulty is the fixing up of the quantum of water that flows in the river.

In this particular case, the quantum of water flowing in the river has been agreed to as between the three parties. That is a great thing which has been done. Normally they could have easily agreed in regard to the quantum at one point. But in this case, actually, they have agreed at three vital points, namely Krishnarajasagar, Mettur and Lower Anicut. These are the three very important points which have got a bearing on the settlement of the allocation of water between the various States, and I am happy that on this matter, at these three points, at the very first meeting, after the fact-finding committee published their report, the

[Dr. K. L. Rao]

three Chief Ministers have agreed to it. That is half the battle won.

Then comes the question of allocation of these waters. When they came to the allocation of water, what the hon. Member said was this. The fact-finding committee has given some figures in regard to the area involved, that is, the cropped area in the Cauvery basin, that is, the area that has been irrigated in the various States and the amount of water that has been utilised. They have taken these figures from those that have been given to them by the various States. They have not verified them from any other statistical facts, but they have simply taken the figures given by the States.

One of the important factors in allocation of water will be the percentage of irrigation that has been done in the various States, how much per cent has been irrigated in Tamil Nadu, how much in Mysore and how much in Kerala. That is a very important factor in the allocation of waters What the fact-finding committee has said is that they have taken the figures as they were given by the States They could not do anything further, because they were not furnished with any other information Now, the Chief Ministers have agreed to give them all the publications on the subject, such as crop data from the revenue point of view, statistical books and so on, and they have got to verify whether the figures already supplied by the Chief Ministers are comparable or they require any modification In other words, after verification, they must come to an agreement on the cropped areas, the irrigated areas and the water that is also utilised. That is another point. We have also asked the committee to find out what is the amount of water utilised is and whether the utilisation excessive, is too much or too little; to give us their opinion. That is the information we want them to give confidentially to us. So, once we have this information, it will be possible for us to take the next step of allocating the waters among these States.

I attended that meeting and from what I have seen, I have found extreme cordiality and the will to settle this problem among themselves. I only hope that in the course of the next two or three months it will be possible for us to tackle this problem.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, I referred to the agreement of 1924 between Madras and Mysore and the view that the present Mysore Government holds, namely, that the agreement is dead. Does the hon. Minister agree with that view?

DR. K. L. RAO: I did not purposely say anything on that, because I did not want to give my views on it. The 1924 agreement was concluded between the then Madras Government and Mysore; it is for a period of 50 years. I do not want to go into the validity or otherwise of it. We are trying to settle the dispute amicably irrespective of any kind of agreement like that which had been made during the previous periods.

SHRI P. GANGADEB (Angul): Mr Speaker, Sir, the Cauvery river water dispute among the three States of Tamil Nadu, Mysore and Kerala has been a long-drawn wrangle, and the inordinate delay in its settlement is a matter of concern to the nation as a whole. Let us not forget that river waters are very much a precious national resource, and its value we know only in its absence. But the unfortunate part of it is that the series of disputes among the various States over this India water, if I may call it, either of Cauvery water or other inter-State river waters, go to show that even when water is available, its value is not sufficiently recognised. Consequently, water resources are neither conserved for the present generation nor for the posterity to benefit from its usage. Unless a permanent and early solution is found to this perennial problem, and unless that is done we will never have water for our fields, nor power for our industries.

This House is well aware that irrigation and river water management are State subjects under the Constitution. In that set-up, we find each State has its vested interests, whether it is in the use of water or power resources and potentialities. It seems as though, the river water disputes these days are more politics and less economics. What is happening is that, on the one hand, some States fail to utilise the surplus waters available within their borders, and, on the other hand, their neighbours are made to suffer for want of sufficient water. One, therefore, wonders who is to be accused and on whom the responsibility falls to ensure an equitable distribution of water resources all over our country.

The constitutional position is indeed anomalous. Merely on the ground that it is a State subject under the Constitution, can the Centre just sit and watch the dispute to be solved by themselves? In the meantime, while some States suffer for want of water due to scarcity and drought, others just allow the invaluable waters to go waste. It is a very important matter to think of. If I may say so, we are up against a man-made problem. Therefore, the Centre has to find a man-made solution. Let us think in terms of national interests and devise means to solve this problem.

I would, therefore, like to suggest firstly that the Government should consider creating viable economic zones for the management of this vital national wealth like river water. Let us not think in terms of linguistic States which has proved artificial. Let there be devices on the basis of resources and potentialities in this regard.

Secondly, the Constitution should be amended, if necessary, to enable the Central Government to enforce discipline in the use of river waters and to secure an eqitable distribution of available water resources.

Thirdly, we should have a quasi-judicial body; in other words, a permanent inter-State River Water Commission whose awards should be made binding on the parties to the dispute. The Central Government should, therefore, have the constitutional authority to enforce these awards. Otherwise, so long the Centre does not have such a device to enforce its writ on the States, the great talk of water grids, I am afraid, will remain a voice in the wilderness.

Finally, what I wish to convey to the Government is this. Let us not leave water to the visissitudes of politics and State chauvinism, and let us not forget that if we do not maintain our river systems in good shape, in a few years' time, we shall be witnessing silted rivers, more scarcity and more drought. It is, therefore, that I have suggested a high-power body to ensure proper river water management on national interest.

Sir, let me hope that the hon. Minister and the Government will use their good offices for an early and final settlement of the Cauvery River water dispute. With these words, I request the hon. Minister to give his reaction to my suggestions.

DR. K. L. RAO: I thank the hon. Member for the various suggestions which we shall keep in mind. I would only submit that the Government feel that water should be declared as a national asset and we are, therefore, thinking of bringing a measure by which we want to declare water as a national asset in the case of rivers, so that the Government will have considerable voice in directing its utilisation to the best interests of the country as a whole.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर): अध्यक्ष, महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य में कहा है उस से विवाद के सुधार की कोई गुंजाइश लगती नहीं है। जैसा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय भी कहा गया है उन्हें केवल फैक्ट फाइंडिंग तक ही सीमित रखा गया था और वह इस बात के लिए प्रतिबन्धित

[डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय]

थे कि वह किसी प्रकार का कोई रेकमेन्डेशन नही करे। उन्हे यह लिखा गया था—

"The fact-finding committee is only to collect data and not to make any recommendations"

उस म स्पष्ट उन्हे यह लिख दिया गया था। कमेटी के सामने जो कठिनाइया भी उत्पन्न हुई और उन्होन कहा था कि कुछ समय और चाहिए कुछ क्लरिफिकेशस के लिए, कमेटी ने स्वय उस बात के लिए समय मागा था कि और कुछ समय हम दिया जाये जिस से कि कुछ क्लैरिफिकेशन जो रह गए है कुछ डाटाज कलेक्ट करने की बात जो रह गई है उन सब का पूरा कर के एक रिपाट प्रस्तुत की जाये। लकिन वह समय उन्हें नही दिया गया। कमटी न अपनी रिपाट म इस बात का दर्शाया है कि उन का और अधिक समय दिया जाता तो शायद वह पूरा विवरण दे पाते। आज भी विवाद की स्थिति जैसी की वैसी ही बनी हुई है।

जैसे ही 29 अप्रैल का यह मीटिंग समाप्त हुई विभिन्न प्रदेशो के मुख्य मत्रियो द्वारा जो प्रतिक्रियाये व्यक्त की गई वह अलग अलग प्रतिक्रियाएँ है। तामिलनाड के मुख्य मत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसा कि समाचार-पत्रो मे प्रकाशित हुआ उन्होने कहा कि हमारा 1924 का ऐग्रीमेट है वह एग्रीमट आगे भी यथावत बना रहना चाहिए जब तक कि उस म किसी प्रकार का सशोधन न किया जाय या दूसरा ऐग्रीमेट उस के स्थान पर न आए तब तक स्टेटस का रहना चाहिए। लकिन उस के विपरीत मैसूर के मुख्य मत्री का कहना यह है कि चाहे किसी प्रकार का ऐग्रीमट हो या न हो, 1924 का ऐग्रीमट तो 1974 म समाप्त हो जायेगा हमारे यहा पर चलने वाली तीन परियाजनाए—कब्बनी, हेमावती और सारगी ये तीनो परियाजनाए यथावत चलेंगी। इस म किसी प्रकार की कोई रोक नही की जायेगी जब कि तामिलनाडु के मुख्य मत्री का आक्षेप है कि इन परियाजनाओ के कार्यान्वित हो जाने से उनको हानि होगी यद्यपि ये बहुत लम्बे समय से चल रही हैं जिसमे कब्बनी के बारे में तो प्लानिंग कमीशन का अप्रूवल भी है, दूसरो के बारे मे कोई अप्रूवल नहीं है, लेकिन तामिलनाडु के मुख्य मत्री द्वारा हेमावती के बारे मे भी यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार उस के बारे मे किसी न किसी प्रकार से उस को सहायता करते हुए, तथा आवश्यक धनराशि से मदद करते हुए अपना काम कर रही है और तामिलनाडु के पक्ष को कमजोर करने की चेष्टा कर रही है।

मै माननीय मत्री जी से यह जानना चाहता हू कि यह एक छोटा सा जल का विवाद है जो इतने लम्बे समय से चला आ रहा है। इतना समय फैक्ट फाइडिंग मे लगा। इस के बाद फिर कहते है कि दो महीने या तीन महीने बाद कोई मुख्य मत्रियो का सम्मेलन होगा तो कोई विचार करेंगे। फिर से रिपार्ट मागी जायेगी। कुछ प्रकाशित नक्शे हैं कुछ अप्रकाशित नक्शे है। कुछ ऐसे दस्तावेज है जो अब तक सामने नही लाए गए है। उन दस्तावेजो का देख कर फिर उस के बारे मे कोई अग्रिम दिशा सोची जायगी। तो इसके अदर कोई विवाद का हल तत्काल निकल सके इस प्रकार की स्थिति नही लगती है। मैं जानना चाहता हू कि क्या आप इस विवाद का हल करने के बारे म कोई ऐसा फारमूला एडाप्ट करने वाले है नशनल इम्पीरिकल फारमूला जिस के आधार पर जिस मे कि राष्ट्रीय स्तर पर इस के ऊपर विचार किया जा सके? जैसा कि अभी सुझाव भी आया है हम जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति मान कर के और राष्ट्रीय स्तर पर सोच कर के इस विवाद का हल कर सकें इस प्रकार का कोई विचार क्या आप रखते है? क्योकि केवल यह कावेरी के विवाद की बात नही है। नर्बदा का विवाद अलग चल रहा है। वह भी एक लम्बे समय से चल रहा है जिस मे मध्य प्रदेश का अपना पक्ष है और गुजरात का अपना पक्ष है। मध्य प्रदेश के लोग सोचते है कि हमारी इसम बहुत हानि हो रही है, हमारा बहुत ज्यादा फर्टाइल लैड इस मे चला जायेगा। लाखो व्यक्ति बेघरबार हो जायेंगे। हजारो किसान मारे मारे फिरेंगे। गुजरात के लोग कहते है कि हमारा

बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और हमारी बहुत अच्छी सिंचाई की क्षमता बढ़ जायगी। बहुत अच्छा हमारा प्रदेश हरा भरा बन जायेगा। अपना अपना पक्ष है। लेकिन केन्द्रीय सरकार जानबूझ कर ऐसे विवाद खड़ी करती है और विवाद को बनाए रखना चाहती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश का है, बानसागर और सोन नदी का झगड़ा चला आ रहा है। उस का भी विवाद पड़ा हुआ है। लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बैठते है और बार बार विचार करते हैं। कई बार विचार हुआ। लेकिन उसके बारे मे कोई निश्चय नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारे देश के अदर जो जल प्रवाह हो रहा है जिस का हम उपयोग कर सकते है वह हम नही कर पा रहे है। आज चारो तरफ पावर की कमी है। जगह जगह पावर की कटौती की वजह से हमे बहुत काफी कठिनाइया हो रही है। इरीगेशन फैसिलिटीज कही पर पाच परसेंट, कही दस परसेंट और कहीं आठ परसेंट है। पजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाये तो पूरे देश भर के अन्दर आठ या दस प्रतिशत से ज्यादा इरीगेशन फैसिलिटीज नही है।

ऐसी हालत मे ऐसे मामले के अदर सरकार ढिलाई करे और इसके बारे मे कोई सक्त कार्यवाही न करे, यह ठीक नही है। मै माननीय मत्री जी से कहना चाहता हू कि यूरोप के अदर डैन्यूब नदी बहुत बड़ी है जो यूरोप के कई देशों के अदर से होकर बहती हुई गुजरती है। वहा पर समझौता हो सकता है। परस्पर एक दूसरे देश जल का बटवारा कर सकते है। लेकिन हमारे अपने देश के अदर दो तीन प्रदेश मिल कर जल का बटवारा नही कर सकते है और आप करवाने मे समर्थ नही हो सकते है। आप चाहते है कि इस प्रकार के विवाद बने रहे ताकि यह समस्या खड़ी रहे और लोग बार बार आप के पास आए। मैं एक बात और मत्री महोदय से जानना चाहूगा कि आखिर यह जो मुख्य मत्रियो का सम्मेलन वह बुलाने जा रहे है वह कब बुला रहे हैं और फैक्ट फाईंडिग कमेटी को फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं तो यही समिति होगी, उसके सदस्य यही होगे या कुछ नये लोगो को इस मे लेने जा रहे है? आप यह समिति कब तक पुनर्गठित करने जा रहे हैं? और फिर जब तक कि फैक्ट फाइंडिग कमेटी आप रिवाइव नही करते है जब तक कोई नया गठन उसका नही हो जाता है, जब तक कि आप अपना कोई निर्णय नही देत हैं तब तक क्या 1924 का ऐग्रीमेंट यथावत कायम रहेगा या जैसा कि मैसूर राज्य ने जो कहा है कि हम अपनी परियोजनाए यथावत चालू रखेगे तो वह रख सकेंगे या नही रख सकेंगे? उसके कारण तामिलनाडु पर उस का कोई विपरीत प्रभाव तो नही पड़ेगा? या मैसूर के अदर उससे कोई विपरीत प्रभाव तो नही पड़ेगा? क्यो कि मैसूर का कहना है कि हम को जितना जल मिलना चाहिए और जितना जल मिल रहा था, जितने के हम अधिकारी थे, हम उतने का ही उपयोग कर रहे है, हम उस से अधिक का उपयोग नही कर रहे है। मैसूर वाले यह कहते है। लेकिन इन परियोजनाओ के बाद भी क्या उन का यह दावा सही है? और यदि सही है तो उन को यह हक मिलना चाहिए। यदि तामिलनाडु के ऊपर इस का विपरीत असर पड़ता है तो सरकार को उस को भी देखना चाहिए। इन सारी बातो के बारे से मैं माननीय मत्री जी का उत्तर चाहता हू कि भविष्य मे इन सभी बातो के उपर ध्यान रखते हुए वह कौन सा कदम उठाने जा रहे है? और जो स्पष्टत मैंने कहा 1924 के ऐग्रीमेंट के बारे मे उस ऐग्रीमेंट को रखना चाहते है या नही रखना चाहते हैं, उस के बारे मे भी बताए। जो मैसूर की परियोजनाए है उसके बारे मे उन का क्या विचार है और केरल ने जो अपना दावा प्रस्तुत किया है उस के बारे मे उनका क्या विचार है?

वर्तमान कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अब जो जल प्राप्त हो रहा है वह 21 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राप्त हो रहा है, लेकिन 35 मिलियन क्यूबिक मीटर का दावा किया जा रहा है, 14 मिलियन कैसे बढ़ गया यह कहा से आवेगा? इस के बारे मे क्या ओवरलैपिग हो रही है, दूसरे प्रदेशो ने अपने दावे बढ़ा चढ़ा कर रखे हैं, इन सब मामलो को आप कब तक समाप्त कर पायेंगे? कृपया उक्त तथ्यो का स्पष्ट उत्तर दे।

DR K L RAO Sir, I do not know what exactly the Chief Ministers said outside the meeting But this is what they have agreed to and, according to their statement There was a general consensus on the total yield of the river as given in the Fact-Finding Committee's report The Committee has been asked to furnish clarifications on some other points after such verification as is found necessary The Chief Ministers agreed to meet at a later date to continue the discussions and explore the possibilities of arriving at a settlement, is agreed upon on 31st May, 1972

This was the statement issued after the meeting Therefore I expect that after the clarifications in respect of certain points that are found necessary are received, they will be able to discuss them and arrive at an amicable solution As I submitted we are expecting verified data for the committee in one or two months time Immediately after that Chief Ministers will meet and I hope that there would be good progress in finding a solution

As regards the observations made by the hon Member in regard to inter State disputes in a country like ours with so many rivers flowing through many States the disputes are very small in number Most of these disputes would be solved In the case of the Narmada water dispute the concerned States are awaiting the award of the Prime Minister As regards Bansagar Dam on the river Sone, we are continuously discussing it We hope that a solution in the best interests of the States, would be evolved

As regards river water disputes I should say that there are not so many disputes pending before tribunals All this is a very healthy sign We are able to adjust ourselves on such a vital matter Similarly, in the case of Cauvery water, this is of course a difficult problem, the demand for water by the States is very much more than available in the river, rightly so That shows that they are interested in improving the irrigation and they want water for that purpose It is a very desirable thing It is in this context that a national water grid is necessary so that water may flow to deficit areas of the States I feel that we should congratulate ourselves that there have not been many water disputes

---

12 34 Hrs.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of Delhi Transport Corporation 1971-72, Annual Report and certified Accounts of Shipping Development Fund Committee for 1971-72, Delhi Motor Vehicles (2nd Amdt ) Rules, 1972 and notifications under Motor Vehicles Act, 1939 in respect of Andhra Pradesh

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) I beg to lay on the Table —

(1) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Delhi Transport Corporation New Delhi for the year 1971 72 under sub section (3) of section 35 of the Road Transport Corporations Act 1950 [*Placed in Library See* No LT 4964/73]

(2) A copy of the Report and Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Shipping Development Fund Committee for the year 1971 72 together with the Audit Report thereon, under sub-section (6) of section 16 of the Merchant Shipping Act, 1958 [*Placed in Library See* No LT-4965/73]

(3) A copy of the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No F 3 (28)/72 Tpt in Delhi Gazette dated the 1st January, 1973 under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939 [*Placed in Library See* No LT-4966/73]